भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2383

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

भू-जल की कमी

2383. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने 64.6 बीएन एम3 भूजल की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक सहित देश भर में भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर देश के डॉयनेमिक भूमि जल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में किए गए आकलन से वर्ष 2024 के आंकड़ों की तुलना करने पर, यह पाया गया है कि इस अवधि के दौरान देश में कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 393 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 406 बीसीएम हो गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि जल निष्कर्षण (एसओई) का चरण, जिसे कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूमि जल संसाधनों की तुलना में सभी प्रयोजनों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, इसी अवधि के दौरान 63% से घटकर 60.47% हो गया है। यह क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद देश की भूजल स्थिति में समग्र सुधार को प्रदर्शित करता है।

(ग): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित विषयों पर कार्य करने का दायित्व मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कर्नाटक राज्य सहित देश के भूजल संसाधनों में सुधार के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया

जा रहा है, जिसमें कर्नाटक के जल की कमी वाले 10 जिलों सहित देश के 151 ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण करते हुए विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में कर्णाटक में लगभग 15.88 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत्त विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। कर्नाटक के 1.91 लाख वर्ग किमी सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी मैपिंग योग्य क्षेत्र में इस योजना के तहत मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कर्नाटक सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 को तैयार किया गया है और इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल के संरक्षण के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इस मास्टरप्लान में कर्नाटक के लिए लगभग 61,225 संरचनाओं की सिफारिश की गई है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित स्कीम है, इन राज्यों में कर्नाटक भी शामिल है।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से कर्नाटक सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य जल भंडारण बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इस मिशन के परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 4,056 कर्नाटक में हैं।

vii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग

से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

viii. भूजल संबंधी जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अब तक कुल 93 सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) और 50 टियर- II और टियर -III प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

*****